PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 022
दि. 22.05.2026, शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिली खुशखबरी, महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश

(जीएनएस)।

लखनऊ। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सुधि ली है।

राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा जून में मिलने वाली सैलरी और पेंशन में दिखाई देगा।

उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद कुल डीए 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

सराकर के इस फैसले से राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में दो

प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिला है।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच कर्मचारियों की आय में राहत देने वाला माना जा रहा है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी आदेश के बाद लिया गया है।

जून की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा

सरकार की तैयारी है कि मई 2026 के वेतन के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दें। मई महीने का वेतन जून की शुरूआत में कर्मचारियों के खातों में आता है, इसलिए जून में मिलने वाली सैलरी में इसका सीधा असर दिखेगा। कर्मचारियों की सैलरी पहले से अधिक होगी।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीते दिनों दो प्रतिशत बढ़ी दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत (डीए/डीआर) देने का आदेश तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री को ईमेल में उन्होंने लिखा है कि यूपी देश का पहला राज्य है जो सबसे पहले अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत देता रहा है। केंद्र सरकार ने एक जनवरी से बढ़ी दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है।

प्रदेश में प्रचंड गर्मी को देखते हुए अलर्ट पर सरकार, सीएम योगी ने दिए बिजली- अस्पताल को लेकर ये निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ , मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के दृष्टिगत अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें तथा किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए।

सीएम ने अधिकारियों को अस्पतालों, पेयजल व्यवस्था और बिजली आपूर्ति की लगातार निगरानी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी में अधिक परेशानी बिजली कटौती और पानी की कमी से होती है। सभी डीएम अपने जिलों में नियमित समीक्षा करें और समस्याओं का तत्काल समाधान कराएं। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के इंतजाम रहें। आवश्यक दवाएं, बेड, आईवी फ्लूइड और डॉक्टरों की उपलब्धता हो। एंबुलेंस

सेवाओं को भी सक्रिय रखा जाए। बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। दोपहर में बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर न जाने दें। बुजुर्गों को भी तेज धूप से बचाने के साथ नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। ढीले सूती कपड़े पहनें जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। अधिक से अधिक पानी ओआरएस और नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें तथा धूप में निकलते समय सिर को ढकें।

आग से बचाव का रहे इंतजाम

सीएम ने कहा कि गर्मी में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है। खेतों, बाजारों, गोदामों और रिहायशी इलाकों में अग्नि सुरक्षा उपायों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। ऐसी कोई भी लापरवाही न हो, जिससे आग लगने का अंदेशा हो। फायर विभाग पूरी तैयारी रखे। निर्माण कार्यों और खुले स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों को लू, थकावट और निर्जलीकरण से बचाने के कदम उठाएं। कार्यस्थलों पर पेयजल, छाया व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो। श्रमिकों से लगातार काम न कराया जाए। सभी विभाग किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी रखें। आमजन को गर्मी व लू से बचाव के उपायों के बारे में बताएं।

श्रावणी मेला-2026: बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार सतर्क, 30 जून तक सभी मेंटेनेंस कार्य पूरे करने के निर्देश

श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित

करने के लिए बिहार सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को विद्युत भवन, पटना में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में ऊर्जा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को 30 जून 2026 तक सभी विद्युत मेंटेनेंस कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा सचिव सह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अजय यादव ने की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री क्वोन ओह-यूल ने सियोल में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री श्री क्वोन ओह-यूल ने 21 मई, 2026 को सियोल के इमजिनगैक पार्क में संयुक्त रूप से भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निर्मित यह स्मारक, युद्ध के दौरान भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया (सीएफआई) के साहस, बलिदान और मानवीय सेवा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

दोनों मंत्रियों ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिनकी सेवा को कोरिया गणराज्य के लोग आज भी गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं।

रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और मानवीय सहायता के क्षेत्र में भारत के

अमिट योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का साझा इतिहास और बलिदान भारत-कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव बने हुए हैं।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सैनिकों की भूमिका को याद करने से लोगों के बीच आपसी समझ मजबूत होती है और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों पर नए सिरे से ध्यान जाता है। स्मारक की स्थापना में बहुमूल्य सहयोग के लिए उन्होंने कोरिया गणराज्य की सरकार, विशेष रूप से पूर्व सैनिक मामलों के मंत्रालय के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

दक्षिण कोरिया के पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री ने कोरियाई युद्ध के दौरान भारत की भूमिका की सराहना की। उन्होंने भारतीय सैनिकों के बलिदान और मानवीय सेवा के माध्यम से निर्मित अटूट मित्रता के बंधन को स्वीकार किया।

कोरियाई युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को सम्मानित करने और उनके बीच आदान-प्रदान को मजबूत करने के उद्देश्य से दोनों मंत्रियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

गाली-गलौज कमजोरों का हथियार... पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ 'गद्दार' संबंधी टिप्पणी के लिए राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए गुरुवार पीयूष गोयल ने कहा कि उनके बयान उनकी हताशा को दर्शाते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि जनता बार-बार उन्हें नकार रही है और उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को निशाना बनाकर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता के बयान और भाषण उनकी हताशा को दर्शाते हैं। जनता बार-बार उन्हें नकार रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है दूसरी तरफ नकारात्मक सोच वाले राहुल गांधी अपने बयानों और भाषणों में बार-बार अपना यही स्वभाव और चरित्र दिखा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गोयल ने कहा कि यह एक अलग बात है कि भारत की जनता उन्हें एक के बाद एक नकार रही है। उनकी हताशा

और खुद से पैदा की गई भावनाएं और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वह स्पष्ट है। राहुल गांधी की ओर से राजनीतिक हमलों में "देशद्रोह" शब्द के प्रयोग पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया।

क्या नक्सलवाद का खात्मा करना देशद्रोह है या कांग्रेस शासन में वर्षों तक नक्सलवाद को फलने-फूलने देना देशद्रोह है। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार जिस तरह से घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, वह देशद्रोह है। - पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

पीयूष गोयल ने कहा कि क्या वैश्विक मंच पर भारतीय ध्वज का सम्मान करना देशद्रोह माना जाता है, या विदेशों में भारतीय ध्वज का अपमान करना देशद्रोह है। क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना देशद्रोह माना जाता है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा कमजोरी को दर्शाती है। यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उसे अंग्रेजी में गाली-गलौज कमजोरों का हथियार है कहा जाता है।

अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आपको खड़ा होना होगा और लड़ना होगा। जब आरएसएस कार्यकर्ता आपके घरों में आकर मोदी और शाह के बारे में बात करें, तो आपको उन्हें बताना होगा कि उनका संगठन, मोदी और शाह गद्दार हैं। उन्होंने हमारे देश को बेचने की कोशिश की है।

अब मदरसों में भी 'वंदे मातरम्' अनिवार्य! बंगाल सरकार के फैसले से फिर गरमाई राजनीति

पश्चिम बंगाल सरकार ने अब राज्य के मदरसों में भी 'वंदे मातरम्' गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के नए निर्देश के मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी होगा।

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में भी 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य बनाया था।

लखनऊ में 60 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू, चाहे मोहर्रम हो या भंडारा, बिना इजाजत के नहीं होंगे कई काम

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह 60 दिनों तक, यानी 19 जुलाई तक लागू रहेगी। इस दौरान शहर में कई प्रतिबंध लागू रहेंगे।

(जीएनएस)।

लखनऊः शहर और उपनगरीय इलाकों में गुरुवार से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा 60 दिनों के लिए लागू की गई है। यानी इसके तहत 19 जुलाई तक कुछ प्रतिबंध लगे रहेंगे। प्रशासन ने बकरीद, बड़ा मंगल, मोहर्रम आदि धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की है।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाए जाने का आदेश

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार ने जारी किया है। इस आदेश में पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक

संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से आदेश में कहा गया है कि बिना इजाजत के पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होकर ग्रुप बनाने, जुलूस निकालने या सभा करने पर रोक रहेगी। यदि कोई धार्मिक आयोजन करना हो, भंडारा, जुलूस, चल समारोह, मजलिस, संगीत का कार्यक्रम आदि आयोजित करना हो, तो इसके लिए पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है।

चेक बाउंस मामले में शमी को कोर्ट से बड़ी राहत, हसीन जहां ने लगाया था गंभीर आरोप

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बड़े कानूनी विवाद में बड़ी राहत मिल गई है। कोलकाता की अलीपुर अदालत ने शमी को उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर

किए गए चेक बाउंस के मामले में पूरी तरह बरी कर दिया है। अदालत ने मामले की गहन सुनवाई के बाद शमी को 1 लाख रुपये के चेक अनादरण के आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है।

यह कानूनी विवाद साल 2018 में शुरू हुआ था, जब हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसी दौरान उन्होंने अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि शमी ने उन्हें घर के खर्चों के लिए 1 लाख रुपये का एक चेक जारी किया था।

पीएम मोदी की 4 घंटे की 'सुपर मीटिंग' : मिडिल ईस्ट संकट से 2047 प्लान तक, मंत्रियों को मिले टास्क

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई शाम केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के साथ एक लंबी और अहम बैठक की। यह बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली और इसमें सरकार के कामकाज, आने वाले लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक शाम करीब 5 बजे 'सेवा तीर्थ' में शुरू हुई।

इसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल हुए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने से पहले इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को सरकार के बड़े 'मिड-टर्म रिव्यू' के तौर पर देखा जा रहा है।

बैठक बुलाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी?

सूत्रों के मुताबिक सरकार यह जानना चाहती थी कि अलग-अलग मंत्रालयों का काम जमीन पर कितना असर दिखा रहा है। पिछले महीनों में कौन से फैसले लिए गए, उनकी प्रगति क्या है और आगे किन क्षेत्रों पर तेजी से काम करने की जरूरत है, इन्हीं मुद्दों पर फोकस रहा।

बैठक में नौ बड़े मंत्रालयों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। इनमें:

- कॉमर्स मंत्रालय
- पेट्रोलियम मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय

जैसे अहम विभाग शामिल थे।

मंत्रालयों को पहले ही निर्देश दिया गया था कि वे अपने सुधारों को चार हिस्सों में समझाएं:

- कानून में बदलाव
- नियमों में बदलाव
- नीतियों में बदलाव
- काम करने के तरीके में बदलाव

इसके साथ यह भी बताना था कि इन फैसलों का आम लोगों पर क्या असर पड़ा।

पीएम मोदी के विजन में बना स्पोर्ट्स का शानदार ईको सिस्टम, गोरखपुर में बोले सीएम योगी

(जीएनएस)।

गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन पर विजेताओं को पुरस्कृत किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से प्रदेश में स्पोर्ट्स का शानदार इकोसिस्टम विकसित हुआ है, रामगढ़ताल अब वाटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 मई को 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से देश और उत्तर प्रदेश में पिछले 11-12 वर्षों में खेल का बेहतरीन इकोसिस्टम विकसित हुआ है। सरकार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए हर कदम तत्परता से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विकसित हुए बेहतरीन इकोसिस्टम का परिणाम रामगढ़ताल है। 2017 के पहले यह गंदगी और अपराध का गढ़ था। आज यहां रोइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ एशियाड प्रशिक्षण शिविर भी संभव हुए हैं। उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने को प्रेरित किया। खिलाड़ी हमेशा सकारात्मक सोच और टीम भावना से कार्य करता है। सीएम योगी ने 'चरैवेति-चरैवेति' को जीवन का मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं का अभाव था। अब हर गांव में खेल के मैदान, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्टेडियम विकसित हो रहे हैं। खेलो

इंडिया खेलो जैसे कार्यक्रमों से खेल गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ी हैं। वाराणसी और गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

रामगढ़ताल वाटर स्पोर्ट्स की नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में नई पहचान बना चुका है। भारत आज विश्व मानचित्र पर एक मजबूत रोइंग शक्ति के रूप में उभरा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए महिला टीम के प्रशिक्षण हेतु रामगढ़ताल को चुना गया है। प्रशासन को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियों पर वाटर स्पोर्ट्स की समृद्ध संभावना है। बलिया, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

खिलाड़ियों का प्रोत्साहन

सीएम योगी ने बताया कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति विकसित की है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को नौकरी की गारंटी दी गई।

ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ आदि में पदक विजेता 534 खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की गई है। ये नियुक्तियां पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों में हुई हैं। 500 और खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के जरिए नौकरी देने का कार्य शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी।

गोरखपुर के रामगढ़ताल में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में 20 राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना। बालक वर्ग की चैंपियनशिप पर आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की टीम ने आधिपत्य जमाया।

मुख्यमंत्री ने इन टीमों और पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सीएम योगी के नेतृत्व में खेल प्रोत्साहन की सराहना की। सांसद रविकिशन शुक्ल ने गोरखपुर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास पर जोर दिया।

सीएम योगी के नमाज बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कही बड़ी बात, मस्जिदों और ईदगाहों में ही होगी नमाज

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने संबंधी हालिया टिप्पणी के बाद शुरू हुई बहस के बीच कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि ईद-उल-अजहा की नमाज पहले की तरह इस बार भी मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अलग-अलग पालियों में नमाज की व्यवस्था भी की जा सकती है।

योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि नमाज पढ़ना आवश्यक है तो इसे मस्जिदों के भीतर अदा किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि यदि भीड़ अधिक हो तो अलग-अलग 'पालियों' में नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर नमाज पढ़ना जरूरी है तो अलग-अलग पालियों में पढ़िए। हम आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़कों पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुसलमान वर्षों से मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं- खालिद रशीद फरंगी महली

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि 28 मई को होने वाली ईद-उल-अजहा के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मस्जिदों और ईदगाहों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग इमामों के नेतृत्व में अलग-अलग समय पर नमाज अदा कराने की व्यवस्था की जा सकती है। मुसलमान वर्षों से मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करते आ रहे हैं और हमेशा कानून-व्यवस्था का पालन करते रहे हैं, क्योंकि नमाज केवल इबादत ही नहीं, बल्कि अनुशासन भी सिखाती है।

उन्होंने कहा कि वर्षों से सड़कों पर नमाज से परहेज कर मुसलमानों ने यह साबित किया है कि वे एक अनुशासित और सभ्य समुदाय हैं। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सभी समुदायों पर समान नियम लागू करेगी। आदर्श स्थिति यही होगी कि कोई भी समुदाय सड़कों पर जुलूस या धार्मिक आयोजन न करे।

नियम सभी पर समान रूप से लागू हो- यासूब अब्बास

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इस वर्ष भी शिया मस्जिदों में ईद की नमाज की तैयारियां हर साल की तरह की जा रही हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि शिया परंपरा में सामूहिक नमाज अलग-अलग 'पालियों' में अदा करने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सामूहिक नमाज पालियों में नहीं होती। योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर अब्बास ने कहा कि यह इबादत का मामला है और केवल एक प्रकार की इबादत को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। कोई भी जुलूस या धार्मिक गतिविधि जो यातायात बाधित करे, उसे रोका जाना चाहिए।

बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख धर्मगुरुओं ने किया समर्थन

इस बीच, बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख धर्मगुरुओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नमाज केवल साफ-सुथरे और शांत स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए, जहां किसी प्रकार की बाधा न हो। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इस्लाम में नमाज के दौरान इबादत करने वाले और अल्लाह के बीच किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की शांति और एकाग्रता सड़कों या चौराहों पर संभव नहीं है, बल्कि मस्जिदों या घरों में ही हासिल की जा सकती है।

सीएम योगी ने कुछ गलत नहीं कहा- मौलाना खुर्शीद

बरेली की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खुर्शीद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सड़कों पर नमाज का विरोध कर कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्देश का पहले भी पालन किया जाता रहा है और आगे भी किया जाएगा।

बहुसंख्यक समुदाय को 'खुश' के लिए दिया बयान- सैयद मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी

अमरोहा स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद के प्राचार्य मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी ने कहा कि इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करना उचित नहीं माना जाता। बिना आवश्यक अनुमति के कहीं भी नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए और मुसलमान इस बात से अवगत हैं व अधिकांश लोग इसका पालन भी करते हैं। हालांकि, मंसूरपुरी ने यह भी कहा कि मुसलमान नमाज को लेकर सरकारी निदेशों का पालन करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की नमाज संबंधी टिप्पणी ''निराधार'' है और बहुसंख्यक समुदाय को 'खुश' करने के उद्देश्य से की गई राजनीतिक टिप्पणी है।

बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ सहित इन जिलों में खतरनाक लू का अलर्ट

(जीएनएस)।

यूपी में 21 मई को गर्मी का प्रकोप चरम पर रहने वाला है. मौसम विभाग ने बांदा, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में बेहद तेज लू और गर्म रातों की चेतावनी जारी की है. दिन में झुलसाने वाली हवाएं और रात में भी बढ़ा तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है. फिलहाल 23-24 मई के बाद कुछ इलाकों में हल्के बदलाव और आंशिक राहत के संकेत मिल रहे हैं.

यूपी में मई की गर्मी अब जानलेवा होने लगी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा चेतावनी के अनुसार 21 मई को प्रदेश के कई जिलों में बेहद तेज और खतरनाक लू चलने की संभावना है. हालात ऐसे बन सकते हैं कि दिन में सड़क पर निकलना मुश्किल होगा और रात में भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिलेगी. मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले घंटे लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

बुंदेलखंड और मध्य यूपी में सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के मुताबिक बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिजार्पुर, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के इलाकों में बहुत तेज लू चल सकती है. इन जिलों में दोपहर के समय हालात सबसे ज्यादा कठिन रहने की आशंका है. सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि दोपहर तक गर्म हवाएं सीधे चेहरे पर आग जैसे थपेड़ों का एहसास कराएंगी. मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में तापमान लगातार सामान्य से ऊपर बना हुआ है.

पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी भी चपेट में

प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, फरुर्खाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और कासगंज में भी बेहद गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन जिलों में भी लोगों को दिनभर झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. पश्चिमी यूपी के शहरों में गर्म हवा और धूलभरी तपिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. वहीं पूर्वांचल के जिलों में उमस और गर्मी मिलकर हालात को और मुश्किल बना सकते हैं.

इन जिलों में भी चलेगी तेज लू

गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में भी तेज गर्म हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में दोपहर के समय बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. खुले मैदानों और सड़कों पर गर्मी का असर ज्यादा महसूस होगा.

रात में भी नहीं मिलेगी राहत

इस बार सबसे बड़ी चिंता सिर्फ दिन की गर्मी नहीं, बल्कि गर्म रातें भी हैं. मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में रात के समय भी ज्यादा गर्मी रहने की चेतावनी दी है. आमतौर पर रात में तापमान गिरने से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इस बार रात में भी गर्म हवाएं और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. बिना कूलर और एसी वाले घरों में हालात ज्यादा कठिन हो सकते हैं.

स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर

लगातार बढ़ती गर्मी लोगों की सेहत पर भी असर डाल सकती है. डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर ढककर बाहर निकलने को कहा गया है.

शहरों में दोपहर का सन्नाटा

भीषण गर्मी का असर अब शहरों की रफ्तार पर भी दिखने लगा है. दोपहर होते-होते बाजारों में भीड़ कम होने लगती है और सड़कें सूनी दिखाई देने लगती हैं. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. कई इलाकों में सुबह 10 बजे के बाद ही धूप चुभने लगती है. वहीं दोपहर में चलने वाली गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है. अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह तेज गर्मी और लू का असर बना रह सकता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह मानने की जरूरत है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लापरवाही भी स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है.

26 मई तक सामूहिक छुट्टी पर रहेंगे लखनऊ के वकील, पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लिया फैसला

17 मई 2026 की पुलिस कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने 21 से 26 मई तक सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, दर्ज मुकदमे वापस लेने और अधिवक्ताओं के हितों से जुड़ी कई मांगें उठाई हैं।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 मई 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने बड़ा फैसला लेते हुए 26 मई तक सामूहिक छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया है। अधिवक्ताओं के हितों और सम्मान की रक्षा को लेकर बुधवार, 20 मई 2026 को सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की संयुक्त आम सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में वकील शामिल हुए। सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले की सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

26 मई तक रहेगा सामूहिक अवकाश

बैठक में अधिवक्ताओं के विचार सुनने और विस्तृत चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। सभा में तय किया गया कि 17 मई की घटना के विरोध में लखनऊ जनपद के सभी अधिवक्ता 21 मई 2026 से 26 मई 2026 तक पूर्ण रूप से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। सभा में वकीलों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

वकीलों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग

अधिवक्ताओं ने वजीरगंज थाने में उनके खिलाफ दर्ज कथित झूठे मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की। इसके लिए शासन और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने को कहा गया है। संयुक्त आम सभा में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि सिविल कोर्ट स्थित पुरानी तहसील परिसर की भूमि सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ को लीज पर दी जाए। इसके अलावा पुराने हाई कोर्ट परिसर में कर्मचारियों के खाली पड़े आवास की भूमि अधिवक्ताओं के चैंबर और पार्किंग निर्माण के लिए उपलब्ध कराने की मांग की गई।

पैरवी के लिए अध्यक्ष और महामंत्री अधिकृत

हाई कोर्ट में लंबित याचिका की 25 मई 2026 को होने वाली सुनवाई के लिए सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल एडवोकेट और महामंत्री अवनीश दीक्षित एडवोकेट को अधिकृत किया गया है। दोनों नेता अधिवक्ताओं की ओर से अदालत में पक्ष रखेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि आंदोलन की अगली रणनीति प्रदेशभर के अधिवक्ताओं के साथ चर्चा के बाद तय की जाएगी। इसके लिए सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ ने 26 मई 2026 को दोपहर 2 बजे फिर आम सभा बुलाने का निर्णय लिया है।

भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं; इनमें सहयोग और विश्वास है: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

वैश्विक संकटों के बीच भी भारत समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देने में सक्षमः श्री गोयल

निर्यात प्रोत्साहन मिशन से लघु एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक उचित प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद मिलेगीः श्री गोयल

हम देश भर में उद्योगों के विकास के लिए क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण अपना रहे हैं; हमने एक समग्र विकास मॉडल तैयार किया हैः श्री गोयल

भारत अगले कम से कम 25 वर्षों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगाः श्री गोयल

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी नवाचार, उच्च परिशुद्धता रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक-दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से सुदृढ़ होती है।

श्री गोयल ने कहा कि पिछले छह महीनों में अमेरिकी उद्योग से अनुमानित 60 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है, जिसमें अमेजन और गूगल जैसी कंपनियों द्वारा किए गए प्रमुख डेटा सेंटर निवेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करता है और वैश्विक स्तर पर अद्वितीय स्तर पर परिमाण, प्रतिभा और बाजार के अवसरों का संयोजन प्रस्तुत करता है।

श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश में है और भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हुए समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कुशल प्रतिभाओं का विशाल भंडार है और 1.4 बिलियन महत्वाकांक्षी भारतीयों, बढ़ती आय और बढ़ते मध्यम वर्ग की मांग के कारण अमेरिकी नवाचार को व्यापक अवसर मिलते हैं।

श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा न्यूनतम है, जिससे साझेदारी और मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि जब पूरकता आपसी विश्वास के साथ जुड़ जाती है, तो यह एक अजेय संयोजन का निर्माण करती है जो भविष्य के लिए विश्वसनीय और गतिशील आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में सक्षम है।

श्री गोयल ने कहा कि सरकार भव्य स्कीम के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण अपना रही है, जिसका उद्देश्य देशभर में 100 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि यह मॉडल औद्योगिक बुनियादी ढांचे को श्रमिक आवास, मनोरंजन और सामाजिक सुविधाओं के साथ एकीकृत करता है ताकि एक समग्र औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो सके।

श्री गोयल ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा, कम लॉजिस्टिक्स लागत और मुक्त व्यापार समझौते मिलकर निवेश, विनिर्माण वृद्धि और निर्यात प्रतिस्पर्धा का एक सकारात्मक चक्र बना रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत अगले कम से कम 25 वर्षों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास का समर्थन करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को शामिल करते हुए समन्वित प्रयास शुरू किए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निर्यात प्रोत्साहन मिशन से लघु एवं मध्यम उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि निर्यात निरीक्षण परिषद, भारतीय मानक ब्यूरो और एफएसएसएआई जैसी एजेंसियां भारत भर में विश्व स्तरीय परीक्षण और गुणवत्ता अवसंरचना के निर्माण के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की गतिशीलता को रेखांकित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह भारत की क्षमता, निर्णायक नेतृत्व और एक विश्वसनीय एवं पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विश्व के साथ जुड़ने के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है।

श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक नेता भारत को प्रशंसा और उम्मीदों की निगाहों से देखते हैं और यह सराहना भारतीयों को एक मजबूत राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को 21वीं सदी की एक निर्णायक साझेदारी बताया, जो अमेरिकी नवाचार और निवेश के साथ-साथ भारतीय कौशल और प्रतिभा के मेल से संचालित है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में हो रहे बदलाव का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर उत्पाद खरीदने और घरेलू स्तर पर असेंबल करने की पुरानी पद्धति से हटकर डिजाइन, नवाचार और बौद्धिक संपदा सृजन का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

दिल्ली-एनसीआर की तरह चमकेगा लखनऊ-एससीआर, 2047 तक बनेंगे 10 नए कॉरिडोर, 6 जिलों में कनेक्टिविटी सुधरेगी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आस-पास के जिलों में रहने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली-ठउफ की तर्ज पर अब यूपी में भी स्टेट कैपिटल रीजन यानी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पूरे इलाके के विकास के लिए 29 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अगुवाई में हुई एक मीटिंग में इस मेगा प्लान पर मुहर लगी। इस पूरी योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ और उसके आस-पास के इलाकों को जोड़ने के लिए 150 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

इन जिलों को मिलाकर बनाया जाएगा हब

सरकार लखनऊ के साथ उसके 5 पड़ोसी जिलों को जोड़कर एक बड़ा बिजनेस और ट्रांसपोर्ट हब बनाने जा रही है। इस नए रीजन में ये 6 जिले शामिल होंगे- लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई।

इन सभी जिलों को आपस में जोड़ने के लिए 'राज्य राजधानी माला' नाम से शानदार सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इससे इन शहरों के बीच आना-जाना बहुत जल्दी और आसान हो जाएगा।

गांवों तक पहुंचेंगी सुविधाएं, थमेगा बड़े शहरों की ओर पलायन

इस मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गांवों तक शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं और तेज कनेक्टिविटी पहुंचेगी, तो लोगों को अपने ही इलाके में रोजगार और

बिजनेस के नए मौके मिलेंगे। इससे युवाओं का बड़े शहरों की तरफ होने वाला पलायन काफी हद तक रुक सकेगा।

नए उद्योगों और बिजनेस से आएगा बड़ा निवेश

इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिर्फ सड़कें और मेट्रो ही नहीं, बल्कि नए उद्योग भी लगाए जाएंगे। इसके तहत बड़े-बड़े लॉजिस्टिक पार्क और फूड पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के किनारे विशेष इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ताकि देश-विदेश की बड़ी कंपनियां यहां आकर निवेश कर सकें।

जानिए कहां-कहां से गुजरेगी नई मेट्रो

आने वाले समय में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए लखनऊ में 10 नए मेट्रो रूट (कॉरिडोर) बनाने को मंजूरी दे दी गई है। यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन को इसकी पूरी डिटेल में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पूरा काम 'विकसित भारत 2047' के तहत चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

इस योजना में शहर के सभी प्रमुख इलाकों जैसे एयरपोर्ट, आईआईएम (IIM), चारबाग और इंदिरा नगर को तो जोड़ा ही जाएगा लेकिन इसके साथ ही जानकीपुरम, मोहनलालगंज, बंथरा और बाराबंकी रोड जैसे नए इलाकों तक भी मेट्रो पहुंचेगी।

कहां और कितनी लंबी बनेगी नई मेट्रो लाइन

कल्ली पश्चिम से आईएमः यह सबसे लंबा रूट होगा, जिसकी लंबाई करीब 45 किलोमीटर होगी। सीजी सिटी से सीसीएस एयरपोर्टः इस रूट की लंबाई 19.8 किलोमीटर होगी। राजाजीपुरम से आईएमः यहां 18.42 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। चारबाग से कल्ली पश्चिमः इस रूट पर 13 किलोमीटर लंबी मेट्रो चलेगी। सीसीएस एयरपोर्ट से बंथराः यहां 11 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जाएगा। इंदिरा नगर से अनोरा कलाः इस रूट की लंबाई 9.27 किलोमीटर होगी। इंदिरा नगर से सीजी सिटीः यहां 7.7 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। मुंशीपुलिया से जानकीपुरमः इस इलाके के लोगों के लिए 6.29 किलोमीटर का रूट बनेगा। कल्ली पश्चिम से मोहनलालगंजः यहां 06 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन प्रस्तावित है।

ये सभी रूट साल 2047 तक अलग-अलग फेज में बजट और प्लानिंग के हिसाब से तैयार किए जाएंगे,

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

ईरान और यूएई अब जानी दुश्मन

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अल दफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में रविवार को एक ड्रोन हमला हुआ और उसके बाद आग लग गई। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ईरान और यूएई अब जानी दुश्मन बन चुके हैं। ड्रोन से बराकाह न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। इस अटैक को यूएई ने बिना किसी कारण के आतंकी हमला बताया। बहरहाल इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी समूह ने नहीं ली है। मगर यूएई का आरोप ईरान की तरफ ही है। यूएई का मानना है कि यह हमला ईरान ने ही ड्रोन के जरिए किया है। पिछले कई दिनों से ईरान-यूएई में तनातनी चल रही है। ईरान का मानना है कि यूएई खुलकर अमेरिका और इजरायल की मदद कर रहा है और उसकी भूमि से ही अमेरिकी हमले हो रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि वर्तमान जंग के दौरान ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मोसाद प्रमुख ने यूएई का गुप्त दौरा किया था। ड्रोन हमले से बराकाह संयंत्र के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक इलैक्ट्रिक जेनेरेटर में आग लग गई। यह आग संयंत्र की भीतरी परिधि के बाहर लगी थी। संघीय परमाणु नियामक प्राधिकरण (एफएएनआर) ने भी इस हमले की पुष्टि की कि आगे से संयंत्र की सुरक्षा या उसके जरूरी सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी यूनिट सामान्य रूप से काम कर रही है। सभी जरूरी एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे सिर्प आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें और अफवाहों से बचें। बयान में ड्रोन हमले के स्त्रोत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। ईरानी सूत्रों का कहना है कि हमने कोई हमला नहीं किया है तो फिर हमला किसने किया? क्या कोई तीसरी शक्ति अपना खेल तो नहीं खेल रही जो दोनों मुल्कों को लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। इससे पहले भी 5 मई को यूएई ने कहा था कि उसके वुछ क्षेत्रों पर ईरान से दागी गईं मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन ईरान की सैन्य कमान ने इस आरोप से इंकार किया था।

ईरानी अधिकारियों ने यूएई के उन आरोपों को भी खारिज किया था जिसमें ईरान पर हमला करने का दावा किया गया था। दरअसल यूएई को ईरान इसलिए अपना दुश्मन मान रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यूएई की धरती का इस्तेमाल करके ही अमेरिका ने उस पर अटैक किए हैं।

बहरहाल इस हमले ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे नाजुक संघर्ष विराम को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ऐसा लग रहा है कि वूटनीतिक प्रयास भी अब काफी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने इस हमले के पीछे के लोगों पर बिना किसी उकसावे के आतंकवादी हमला करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि वह अपनी देश की संप्रभुता पर किसी भी तरह के खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। दक्षिण कोरिया की मदद से बने और 2020 से चालू बराकाह परमाणु संयंत्र अरब दुनिया का एक मात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 20 अरब डालर की लागत से बना यह संयंत्र यूएई की लगभग एक चौथाई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है।

सड़क हादसों पर सीएम योगी सख्तः ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने से अवैध पार्किंग हटाने तक निर्देश

सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा बैठक में अधिकारियों की टॉप टू बॉटम जवाबदेही तय करने, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने, अवैध डंपर, ओवरलोडिंग, डग्गामार बसों और नशे में ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि अब सड़क हादसों की रोकथाम के लिए टॉप टू बॉटम हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों और स्थानों पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें चिह्नित कर वहां हादसों के कारणों की गहन समीक्षा की जाए और प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर इसका असर दिखना चाहिए। इसके लिए परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग (PWD) और जिला प्रशासन को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टंटबाजी, नशे में ड्राइविंग और ओवरलोडिंग पर सख्ती

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों के प्रमुख कारणों में स्टंटबाजी, नशे में ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और अवैध वाहनों की आवाजाही को गंभीर समस्या बताते हुए इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डग्गामार बसों, अवैध डंपरों और बार-बार चालान होने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

साथ ही जिलों में तैनात आरटीओ और एआरटीओ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया ताकि सड़क सुरक्षा नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके।

अफसरों पर तय जवाबदेही

अवैध पार्किंग और अवैध स्टैंड पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अनधिकृत पार्किंग और अवैध वाहन स्टैंड संचालित नहीं होने दिए जाएं। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि ऐसे स्टैंड्स को तत्काल हटवाया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि बसें सिर्फ निर्धारित स्टैंड पर ही खड़ी हों और परिवहन निगम यह सुनिश्चित करे कि केवल फिटनेस प्रमाणित बसें ही सड़कों पर चलें।

ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और त्वरित सुधार

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सीएम योगी ने ढहऊ अधिकारियों को राज्यभर में सड़क हादसों वाले ब्लैक स्पॉट्स चिह्नित करने और उनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने, ट्रैफिक मॉनिटरिंग मजबूत करने और एंबुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

स्कूल वाहनों और सार्वजनिक परिवहन पर निगरानी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिना फिटनेस प्रमाणपत्र कोई भी स्कूल वाहन सड़क पर न उतरे। सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए और परिवहन निगम केवल फिटनेस प्रमाणित बसों का संचालन करे।

सड़क सुरक्षा अभियान से राहत के संकेत

बैठक में यह भी बताया गया कि 'जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट' योजना के तहत पिछले चार महीनों में 566 लोगों की जान बचाई गई है। जनवरी से अप्रैल के दौरान सड़क हादसों में करीब 21% कमी दर्ज की गई, जबकि हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में 22% गिरावट आई है। सरकार इसे सड़क सुरक्षा अभियानों का सकारात्मक असर मान रही है।

जनजागरूकता अभियान भी होगा तेज

सीएम योगी ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और सुरक्षित ड्राइविंग नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जेब में सिर्फ 2000 रुपए? फिर भी लखनऊ के आसपास घूम सकते हैं ये खूबसूरत जगहें

(जीएनएस)।

लखनऊ के आसपास कई ऐसी जगहें हैं जहां सिर्फ 2000 रुपए के बजट में घूमने का मजा लिया जा सकता है। इनमें नैमिषारण्य, अयोध्या, दुधवा नेशनल पार्क, कानपुर और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जैसी जगहें शामिल हैं। यहां कम खर्च में घूमने, खाने और फोटोग्राफी का शानदार अनुभव मिलता है। घूमने का मन तो हर किसी का करता है, लेकिन कई बार बजट की वजह से लोग ट्रिप प्लान नहीं कर पाते। खासकर छात्रों और नौकरी करने वाले लोग अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहां कम पैसों में अच्छा घूमने का अनुभव मिल सके। दिल्ली एनसीआर के पास तो कई स्थल हैं जहां आप बजट ट्रिप के लिए जा सकते हैं लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ से अगर सफर की शुरूआत करनी हो तो कम पैसों में कहां घूमने जाएं?

अगर आप भी लखनऊ में रहते हैं और वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अच्छी खबर यह है कि शहर के आसपास कई ऐसी शानदार जगहें मौजूद हैं जहां सिर्फ 2000 रुपए के अंदर आराम से ट्रिप पूरी की जा सकती है।

इन जगहों की खास बात यह है कि

यहां पहुंचने का खर्च कम है और प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक शांति या एडवेंचर का भरपूर मजा मिलता है। कहीं जंगल सफारी है, तो कहीं ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल। दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ कम बजट में यादगार ट्रिप प्लान करने वालों के लिए ये जगहें बिल्कुल परफेक्ट हैं।

अगर आप भी कम खर्च में शानदार यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे लखनऊ के आसपास की कुछ ऐसी जगहों के बारे में, जहां 2000 रुपए में आराम से घूमकर आया जा सकता है।

नैमिषारण्य

उत्तर प्रदेश का सबसे पवित्र स्थल माना जाने वाला नैमिष धाम लखनऊ से करीब 90 किमी दूर है। यहां शांति और आध्यात्म का अनोखा अनुभव मिल सकता है। नैमिषारण्य धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां चक्रतीर्थ, गोमती नदी और प्राचीन मंदिर देखने लायक हैं। बस या बाइक से यहां कम खर्च में आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक दिन की ट्रिप के लिए यह जगह बेहतरीन मानी जाती है।

अयोध्या

कम बजट में शानदार धार्मिक यात्रा के लिए अयोध्या जाएं। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या घूमने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लखनऊ से ट्रेन या बस के जरिए यहां बेहद कम खर्च में पहुंचा जा सकता है। सरयू घाट की शाम की आरती और मंदिरों की खूबसूरती यात्रा को यादगार बना देती है। स्ट्रीट फूड का स्वाद भी यहां का बड़ा आकर्षण है।

दुधवा नेशनल पार्क

जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव चाहिए तो लखनऊ और आसपास वाले दुधवा नेशनल पार्क रवाना हो जाएं। नेचर और वाइल्डलाइफ को पसंद करने वालों के लिए दुधवा नेशनल पार्क शानदार विकल्प हो सकता है। यहां हिरण, हाथी और कई दुर्लभ पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलता है। दोस्तों के साथ रोड ट्रिप के लिए यह जगह काफी लोकप्रिय है। बजट में रहने के लिए आसपास सस्ते होटल और गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं।

बिठूर

लखनऊ से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर कानपुर में घूमने की कई जगहे हैं। लेकिन आप गंगा किनारे बसे बिठूर की यात्रा पर जा सकते हैं। कम बजट में यहां की ट्रिप यादगार बन जाएगी। बिठूर में आप गंगा घाट पर स्नान कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और कई ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखने वाले घाट घूम सकते हैं। गंगा किनारे स्थित ब्रह्मवर्त घाट पर ब्रह्म जी ने सृष्टि की रचना की थी। यहीं उन्होंने मनु और श्रद्धा को उत्पन्न किया था। इसके अलावा यहां ध्रुव टीला है, जहां बालकाल्य में ध्रुव ने 99 साल तक तप किया था, ताकि ईश्वर की गोद में बैठ सकें। लवकुश की जन्मस्थली और ऋषि वाल्मीकि का आश्रम भी बिठूर में ही है। 2000 रुपये से कम में यहां की यात्रा आसानी से पूरी की जा सकती है।

नवाबगंज बर्ड सेंचुरी

नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर स्थित उन्नाव जिले में है। लखनऊ से 43 किमी का सफर तय करके यहां पहुंचा जा सकता है। यह स्थान 250 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों का घर है। यह बर्ड सेंचुरी प्रकृति प्रेमियों के लिए बेस्ट जगह है।

अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर शांति चाहते हैं, तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जा सकते हैं। यहां हरियाली, झील और अलग-अलग पक्षियों की खूबसूरती देखने को मिलती है। फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए यह लो-बजट डेस्टिनेशन काफी शानदार माना जाता है।

गुंटूर से आए स्कूली छात्रों ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की

उपराष्ट्रपति ने सरकारी स्कूलों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का आ'ान किया

उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा- 'ईमानदारी से कड़ी मेहनत करो, सफलता में विनम्र रहो'

(जीएनएस)।

आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के स्कूली छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति श्री सी.पी राधाकृष्णन से मुलाकात की।

सरकारी स्कूलों के 27 लड़कियों सहित 41 मेधावी छात्रों के इस समूह ने कक्षा 10 की परीक्षाओं में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था और वर्तमान में वे दिल्ली के शैक्षिक दौरे पर हैं।

सरकारी स्कूल के गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को शैक्षिक दौरे पर दिल्ली लाने की पहल की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे दौरे छात्रों को कक्षा से बाहर सीखने और उनके ज्ञान का विस्तार करने में मदद करते हैं। उन्होंने छात्रों से बातचीत करके खुशी व्यक्त की।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि सभी सफल लोगों को जीवन में संघर्ष, असफलता और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कठिनाइयां किसी व्यक्ति को अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और सफलता के प्रति अधिक दृढ़ संकल्पित बनाती हैं। छात्रों को अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से निराश न होने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा

कि शिक्षा उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएगी।

उपराष्ट्रपति ने छात्रों को याद दिलाया कि देश के कई महान वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षक, नवप्रवर्तक, उद्यमी और राजनीतिज्ञ सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों से ही निकले हैं।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने बताया कि उन्होंने भी एक सरकारी स्कूल में तमिल माध्यम में पढ़ाई की थी और इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा जीवन को बदलने, परिवारों को ऊपर उठाने, समुदायों को मजबूत करने और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देने का सबसे शक्तिशाली साधन है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी स्कूलों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने सांसदों और विधायकों से सरकारी स्कूलों के सुधार और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया।

पिछले एक दशक में देश की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित भारत के सपने की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में छात्रों के सपने और आकांक्षाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि 41 मेधावी छात्रों में से 27 लड़कियां थीं। उन्होंने कहा कि यह देश में नारी सशक्तिकरण को दर्शाता है।

उपराष्ट्रपति ने छात्रों को मादक पदार्थों और हानिकारक व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी, जिनमें सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी शामिल है। उन्होंने छात्रों से खेलकूद, पठन-पाठन और रचनात्मकता को प्राथमिकता देने तथा अपनी पढ़ाई, लक्ष्यों और परिवार एवं राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। अपने संबोधन के समापन में, उपराष्ट्रपति ने छात्रों को तीन सिद्धांतों को हमेशा याद रखने की सलाह दीः ईमानदारी से कड़ी मेहनत करना, सफलता में विनम्र रहना और ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना। उन्होंने सभी छात्रों को उज्ज्वल, सार्थक और सफल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्र शेखर और पश्चिम गुंटूर विधानसभा की सांसद श्रीमती गल्ला माधवी उपस्थित थीं।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों के लिए सुलभ और समावेशी वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने वैश्विक अभिगम्यता जागरूकता दिवस (जीएएडी) 2026 के अवसर पर दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों के लिए सुलभ और समावेशी वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। डीएफएस ने बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए अभिगम्यता मानक और दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें दिव्यांगजनों द्वारा भौतिक माध्यमों, डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिजीटल माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

डीएफएस इस बात पर जोर देता है कि सुलभता केवल एक अनुपालन आवश्यकता नहीं है, बल्कि ग्राहक अनुभव, डिजिटल समावेशन और समान वित्तीय भागीदारी का एक अनिवार्य घटक है। नीतिगत समर्थन और इस विषय पर समय-समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से, वित्तीय संस्थानों को सुलभता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि सेवा वितरण और डिजिटल परिवर्तन के हर चरण में सुलभता को एकीकृत किया जा सके। इस अवसर पर डीएफएस सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और हितधारकों से एक निर्बाध और समावेशी वित्तीय परितंत्र के निर्माण की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने की अपील करता है, ताकि कोई भी ग्राहक पीछे न छूट जाए।

केरल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारी जोरों पर, महिलाओं के लिए समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम

कोट्टायम में योग और आयुर्वेद के माध्यम से रजोनिवृत्ति के दौरान स्वास्थ्य लाभ पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया

(जीएनएस)।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 की 32 दिवसीय तैयारी के हिस्से के रूप में, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से यंग विमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईडब्ल्यूसीए) कलाथिपाडी द्वारा "रजोनिवृत्ति के लिए योग - एक समग्र कल्याण मॉड्यूल" पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में योग और आयुर्वेद की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में समुदाय के सदस्यों, योग अभ्यासकताओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस कार्यक्रम में रजोनिवृत्ति के दौरान स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों, शास्त्रीय योगिक अभ्यासों, प्राणायाम, विश्राम तकनीकों और ध्यान-आधारित उपायों को एकीकृत करने पर विषयगत सत्र शामिल थे।

इस सत्र में रजोनिवृत्ति को एक प्राकृतिक अवस्था के रूप में उजागर किया गया, जिसमें हार्मोनल, भावनात्मक और चयापचय संबंधी परिवर्तन शामिल होते हैं। सत्र में यह बताया गया कि योग शारीरिक आराम, भावनात्मक संतुलन, तनाव कम करने, बेहतर नींद और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकता है।

प्रतिभागियों को ताड़ासन, बद्ध कोणासन, बालासन, सेतु बंधासन, विपरीत करणी और शवासन सहित सौम्य योग की परंपराओं के साथ-साथ नाड़ी शोधन और भ्रामरी जैसी प्राणायाम तकनीकों से परिचित कराया गया, जो तंत्रिका तंत्र के संतुलन और मानसिक कल्याण में सहायता के लिए जाने जाते हैं।

इस कार्यक्रम में वात असंतुलन और धातु क्षय पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य के लिए सहायक आहार और जीवनशैली पर जोर दिया गया।

डॉ. मलयिल साबू कोशी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भारत की वाईडब्ल्यूसीए, सीएमएस कॉलेज और कोट्टायम नगर प्रशासन के अन्य विशिष्ट अतिथि और वक्ता भी उपस्थित थे।

इस आयोजन ने महिलाओं के स्वास्थ्य में एक निवारक, प्रोत्साहक और चिकित्सीय माध्यम के रूप में योग की भूमिका को सुदृढ़ किया, जो पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सामुदायिक स्वास्थ्य और जीवनशैली में एकीकृत करने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने मिशन लाइफ अभियान के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ चिड़ियाघर के शिक्षा केंद्र में ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम (एसवीपी) 2026 का सफल शुभारंभ किया।

मिशन लाइफ के जन-जागरूकता अभियान के तहत आयोजित यह कार्यक्रम 'प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए।' विषय पर आधारित विश्व पर्यावरण दिवस थीम के अनुरूप है। इसका उद्देश्य युवा छात्रों में जैव विविधता संरक्षण, जलवायु कार्रवाई, वन्यजीव संरक्षण, स्वच्छता और सतत जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए इंटरैक्टिव शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से कुल 854 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। इनमें से 60 प्रतिभागियों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया गया और पुष्टि के लिए उनसे फोन पर संपर्क किया गया। उद्घाटन दिवस पर दिल्ली-एनसीआर के 15 स्कूलों के 39 छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम के पहले दिन प्रतिभागियों को एसवीपी 2026 के उद्देश्यों और गतिविधियों से परिचित कराने के लिए ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के बाड़ों का भ्रमण कराया गया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की पूर्व संध्या पर डॉ. फैयाज ए. द्वारा जैव विविधता पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान भी दिया गया।

यह दो सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम दो स्लॉट - स्लॉट ए और स्लॉट बी - में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक स्लॉट में 50 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 25 जूनियर और 25 सीनियर छात्र हैं।

कार्यक्रम की रूपरेखा में शैक्षणिक और रचनात्मक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे कि वन्यजीव फोटोग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट, हेरिटेज वॉक (धरोहर यात्रा), स्लोगन लेखन, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं, स्वच्छता जागरूकता अभियान, क्ले मॉडलिंग (मिट्टी के मॉडल बनाना), निबंध लेखन, प्रदर्शनियां, विशेषज्ञ वार्ता और मिशन लाइफ जागरूकता सत्र।

यह ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 21 मई से 6 जून 2026 तक जारी रहेगा, जो कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को व्यावहारिक शिक्षणऔर संरक्षण शिक्षा से जोड़ेगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय में अब एग्जाम कॉपियों के मूल्यांकन में होगी स्टेप मार्किंग, लाखों छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ

(जीएनएस)।

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली बार सभी विषयों में 'स्टेप मार्किंग' की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इस निर्णय से विश्वविद्यालय के लाखों परीक्षार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

नई व्यवस्था के अंतर्गत अब सब्जेक्टिव (विषयपरक/निबंधात्मक) प्रश्नपत्रों के उत्तरों को विभिन्न मुख्य बिंदुओं और चरणों में विभाजित कर जांचा जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी का अंतिम उत्तर किसी कारणवश त्रुटिपूर्ण भी होता है, लेकिन उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और शुरूआती चरण सही हैं, तो उसे प्रत्येक सही चरण के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे।

इस कदम से किसी भी विद्यार्थी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने द्वितीय परिसर में सभी विषयों के मूल्यांकन प्रभारियों के साथ बैठक में लिया।

कुलपति ने कहा, अक्सर यह देखा जाता रहा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं की अधिक संख्या होने के कारण मूल्यांकन में एकरूपता की कमी रह जाती है, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र को कई सारे परीक्षक जांचते हैं और सबका नंबर देने का तरीका अलग-अलग होता है

जिससे विद्यार्थियों के अंकों में विसंगतियां आने की आशंका बनी रहती थी।

इसलिए मूल्यांकन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। मूल्यांकन में पूर्ण एकरूपता बनाए रखने के लिए पहली बार मुख्य परीक्षक और उप-मुख्य परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

प्रत्येक विषय में कितने मुख्य परीक्षक और डिप्टी हेड नियुक्त किए जाएंगे, इसका निर्धारण पूरी तरह से उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या के आधार पर किया जाएगा। किस विषय अथवा प्रश्नपत्र में कितने मुख्य परीक्षक नियुक्त होंगे, उनके नामों का चयन संबंधित विभागाध्यक्ष करेंगे।

हर परीक्षक को 50 कॉपी जांचना अनिवार्य

मूल्यांकन कार्य शुरू होने से पूर्व सभी मुख्य परीक्षक प्रत्येक प्रश्नपत्र सब्जेक्टिव का एक प्रामाणिक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के 'की वर्ड' निर्धारित किए जाएंगे, जिसके आधार पर ही सभी परीक्षक कापियों का मूल्यांकन करेंगे।

कॉपियों की सुचारू जांच सुनिश्चित करने के लिए मुख्य परीक्षक प्रत्येक जांचे गए बंडल में से अनिवार्य रूप से कुल उत्तर पुस्तिकाओं के न्यूनतम पांच प्रतिशत कापियों की स्वयं रैंडम जांच करेंगे। पूर्व में उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल 25 कॉपियों के बनाए जाते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर प्रति बंडल 50 कापी कर दिया गया है।

उत्तर पुस्तिकाएं अब परीक्षा केंद्रों से सीधे अधिकृत केंद्रीय एजेंसी को भेजी जाएंगी, जहां से उन्हें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षक के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 50 कापियां जांचना अनिवार्य घोषित किया गया है। मूल्यांकन केंद्रों का समय सुबह छह बजे से ही शुरू हो जाएगा।

अदालत की मंजूरी के बिना अग्रिम जांच मान्य नहीं होगा, लखनऊ हाई कोर्ट बेंच का बड़ा फैसला

(जीएनएस)।

लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने किसी भी मामले की जांच से पहले कोर्ट की मंजूरी को जरूरी करार दिया है। कोर्ट ने एक ही मुकदमे में दोबारा संज्ञान लेना अस्वीकार्य बताया।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने पुलिस की किसी भी केस में एडवांस जांच पर सवाल खड़े किए हैं। हाई कोर्ट बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि कोर्ट की अनुमति के बगैर पुलिस की अग्रिम विवेचना को वैध नहीं माना जा सकता है। साथ ही, कोर्ट ने साफ कहा है कि एक ही केस में दोबारा संज्ञान लेना कानूनन स्वीकार्य नहीं है। सैयद मोहम्मद हमजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला दिया।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट बेंच ने मामले की सुनवाई के क्रम में सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सेकेंड कॉग्निजेंस ऑर्डर और डिस्चार्ज ऑर्डर खारिज करने के आदेश को निरस्त कर दिया। दरअसल, वर्ष 2021 में

अंबेडकरनगर में केस दर्ज हुआ था। पुलिस की ओर से जांच के बाद दाखिल चार्जशीट में याची के खिलाफ हत्या की धारा नहीं लगाई गई थी। बाद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विवेचक ने धारा 302 और 201 आईपीसी में अनुपूरक चार्जशीट दाखिल कर दी।

याची की ओर से इस संबंध में दलील दी गई कि आगे की विवेचना से पहले ट्रायल कोर्ट की अनुमति नहीं ली गई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्रमोद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जांच के पहले अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य है।

सरकार ने भी किया स्वीकार

मामले की सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट में सरकार की ओर से स्वीकार किया गया कि एसपी के आदेश पर आगे की जांच की गई। इसके लिए ट्रायल कोर्ट से पहले कोई अनुमति नहीं ली गई। इस पर पीठ ने कहा कि एक ही केस क्राइम नंबर में दो बार संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, खासकर तब जब ट्रायल पहले से चल रहा हो। हाई कोर्ट की पीठ ने यह भी पाया कि डिस्चार्ज अर्जी खारिज करते समय ट्रायल कोर्ट ने याची के कानूनी तर्कों पर कोई विचार नहीं किया।

हाई कोर्ट ने इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए 29 अप्रैल 2023 की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 3 फरवरी 2026 के सेकेंड कॉग्निजेंस ऑर्डर और 13 फरवरी 2026 के डिस्चार्ज आदेश को निरस्त कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने मामले में यह छूट दी है कि जांच अधिकारी और ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकते हैं।

बस से 10.48 करोड़ की हेरोइन मिली, आरआई ने लखनऊ में यात्री को दबोचा; अब तक 42.68 करोड़ का माल पकड़ा

(जीएनएस)।

लखनऊ , लखनऊ में डीआरआई ने काठमांडू से दिल्ली जा रही बस से 5.24 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर एक यात्री को गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 10.48 करोड़ रुपये बताई गई है। एजेंसी अब तस्करी नेटवर्क और सरगना तक पहुंचने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए काठमांडू से दिल्ली जा रही बस के एक यात्री के पास से 5.24 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10.48 करोड़ रुपये आंकी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

दिल्ली-एनसीआर

डीआरआई अधिकारियों को सूचना मिली थी कि काठमांडू से दिल्ली जा रही बस में यात्रा कर रहा एक यात्री भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने बुधवार तड़के करीब चार बजे लखनऊ में संदिग्ध यात्री को रोककर पूछताछ की।

इसके बाद उसके सामान की गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग में छिपाकर रखे गए दो पैकेट बरामद हुए, जिनमें 5240 ग्राम सफेद पाउडरनुमा पदार्थ मिला। मौके पर किए गए फील्ड टेस्ट में पदार्थ हेरोइन पाया गया।

एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। हेरोइन की खेप दिल्ली में कहां डिलीवर होनी थी। एजेंसी नेटवर्क को संचालित करने वाले सरगना तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले छह महीनों में डीआरआई ने लखनऊ में कुल 21.34 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है, जिसकी अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब 42.68 करोड़ रुपये है।

यूपी में कौशल विकास को नई उड़ान, लखनऊ ITOT में नया वर्कशॉप ब्लॉक शुरू; अब मिलेंगे 10 नए रोजगारपरक कोर्सेज

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ के अलीगंज आईटीआई परिसर स्थित आईटीओटी (ITOT) में अत्याधुनिक 'न्यू वर्कशॉप ब्लॉक-सी' बिल्डिंग का भव्य उद्घाटन किया। 10 नए आधुनिक व्यवसायों (ट्रेड्स) की शुरूआत के साथ यह संस्थान अब प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।

केवल डिग्री नहीं, रोजगार और स्वरोजगार पर फोकस

उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सिर्फ डिग्री बांटना नहीं, बल्कि उन्हें सीधे उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। उन्होंने प्रशिक्षकों से अपील की कि वे छात्रों में आत्मविश्वास जगाएं और पढ़ाई बीच में छोड़ने (ड्रॉपआउट) वाले बच्चों पर विशेष नजर रखें। मंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह कौशल प्रशिक्षण उनके जीवन को बदलने वाला सुनहरा अवसर साबित होगा।

रोजगार के पैमाने पर होगा संस्थानों का मूल्यांकन

इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि सरकार बदलते समय के अनुसार पारंपरिक कोर्सेज की जगह उद्योग आधारित आधुनिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बात साझा करते हुए कहा कि अब किसी भी संस्थान की सफलता केवल इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि वहां कितने बच्चों ने ट्रेनिंग ली, बल्कि मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि वहां से प्रशिक्षण पाकर कितने युवाओं को वास्तव में रोजगार या स्वरोजगार मिला।

ट्रेड्स की संख्या हुई दोगुनी, क्षमता में भारी विस्तार

संस्थान के विकास के आंकड़े साझा करते हुए प्राविधिक निदेशक डी. के. सिंह ने बताया कि नई बिल्डिंग के निर्माण से पहले यहाँ केवल 10 व्यवसाय संचालित थे, जो अब बढ़कर 20 हो गए हैं। ट्रेड्स दोगुने होने से अब संस्थान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या भी लगभग 1300 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही, प्रदेश में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए नवनियुक्त 1781 अनुदेशकों (इंस्ट्रक्टर्स) के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है।

ये हैं नए शुरू हुए आधुनिक ट्रेड्स

न्यू वर्कशॉप ब्लॉक-सी में जिन 10 नए रोजगारपरक व्यवसायों को शामिल किया गया है, उनमें ड्रेस मेकिंग, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, ऑफिस मैनेजमेंट, पेंटिंग टेक्नोलॉजी, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (हिंदी), इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और टर्नर शामिल हैं। ये सभी ट्रेड आज के औद्योगिक बाजार की मांग के अनुरूप हैं, जो युवाओं के लिए नौकरियों के सीधे अवसर खोलेंगे।

कार्यक्रम के अंतिम चरण में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ट्रेनिंग ले रहे छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद कर उनके सुझाव सुने और परिसर में नीम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

मध्यस्थता और पंचनिर्णय में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने पर ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक

(जीएनएस)।

भारत की ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने घोषणा की है कि "मध्यस्थता और पंचनिर्णय में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने पर ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की घोषणा" को आज, 21 मई 2026 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित माननीय न्याय मंत्रियों की बैठक में अपनाया गया।

यह घोषणापत्र, जिसे 19-20 मई 2026 को गांधीनगर में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई, सदस्य देशों में मध्यस्थता और मध्यस्थता को विस्तारित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और

संयुक्त अरब अमीरात के न्याय मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडलों के साथ भाग लिया।

घोषणा के मुख्य तत्वों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी कानूनी अधिकारियों, मध्यस्थों, पंचों, न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों सहित हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण की पहलों को मजबूत करना; एडीआर प्रक्रियाओं की पहुँच, दक्षता और प्रवर्तनीयता को बढ़ाने के लिए संस्थागत मध्यस्थता और पंचनिर्णय सुधारों को बढ़ावा देना; तथा एडीआर में डिजिटल उपकरणों के उपयोग और नवाचार सहित सर्वोत्तम प्रथाओं पर सहयोग और ज्ञान-साझाकरण को प्रोत्साहित करना शामिल है।

इस घोषणा को अपनाना ब्रिक्स सदस्यों के उस साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जिसके तहत वे मध्यस्थता और पंचनिर्णय को विवादों के समाधान के लिए पसंदीदा माध्यमों के रूप में अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना चाहते हैं; ऐसा करके वे अदालतों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने और व्यापार तथा निवेश के लिए एक स्थिर वातावरण तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं।

विधि कार्य विभाग, घोषणा-पत्र की प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए ब्रिक्स भागीदारों के बीच निरंतर सहयोग का स्वागत करता है, और उन अनुवर्ती पहलों तथा सहयोगात्मक परियोजनाओं की अपेक्षा करता है, जो एडीआर के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और संस्थागत सुधारों को क्रियान्वित करेंगी।

नाजिया इलाही खान ने सीएम योगी को फरिश्ता बताया, कहा- भटके हुए मुसलमानों को सही राह पर ला रहे

बीजेपी की नेता नाजिया इलाही खान ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस बात का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने के लिए कहा है। नाजिया ने बताया है कि नमाज कैसे पढ़ी जानी चाहिए।

(जीएनएस)।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को ऐसा नहीं करने की हिदायत देते हुए चेतावनी दी है यदि वे प्यार से नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। बीजेपी की नेता नाजिया इलाही खान ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरिश्ते का रूप धारण कर लिया है। वे भटके हुए मुसलमानों को सही राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ अल्लाह सुभान के फरिश्ते

बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने कहा, 'मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्लाह सुभान के फरिश्ते का रूप धारण कर लिया है। वे भटके हुए मुसलमानों और इस्लामी लोगों को सही इस्लाम और सही कुरान समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे पैगंबर मोहम्मद की कई हदीसें यह कहती हैं कि आपकी इबादत से या आपकी तिलावत से अगर किसी को तकलीफ हो तो अल्ला सुभान उस इबादत को और उस तिलावत को कबूल नहीं फमार्ते हैं।'

नापाक रोड पर नमाज पढ़ने वाले पाखंडी मुसलमान

उन्होंने कहा कि, 'तो जब खुद पैगंबर मोहम्मद इस बात को हदीसों के जरिए बता रहे हैं मुसलमानों को कि आप किसी को अपनी इबादत से और अपनी तिलावत से तकलीफ मत दीजिए, तो ये कौन पाखंडी मुसलमान हैं, ये कौन से झूठे मुसलमान हैं, ये कौन से जेहादी और पाकिस्तानी मानसिकता के मुसलमान हैं जो नापाक रोड पर मुसल्ला और जा-नमाज बिछाने को तैयार हैं।'

रोड पर कैसे ले सकते हैं अल्लाह का नाम?

नाजिया इलाही खान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि, 'जब नमाज की शुरूआत होती है, नीयत बांधी जाती है अल्लाह के नाम से, और जब दुआ के तौर पर खत्म किया जाता है तो अयदुलकुरसी से और सुरेपाकिया से खत्म किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि आप अल्लाह का नाम नापाक रोड पर कैसे ले सकते हैं? मुसल्ला और जा-नमाज पर मक्का मुअज्जम और मदीना मनव्वरा की जो तस्वीर बनी होती है, आप उसे नापाक रोड पर बिछा कैसे सकते हैं? '

घर में क्यों नहीं पढ़ते नमाज?

उन्होंने कहा कि, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। भटके हुए मुसलमानों को और जाहिल मुसलमानों को...जो मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को अपना आका अब नहीं मानकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को अपना आका मान चुके हैं, उनको सही राह पर लाने का काम उन्होंने किया है। सही इस्लाम, सही हदीस, सही कुरान और सही इस्लामिक शरायत बताने की कोशिश उन्होंने की है। रोड पर नमाज बिल्कुल मत पढ़ो। नमाज पढ़नी है तो मस्जिद अल्ला के घर में पढ़ो, ईदगाहों में पढ़ो, करबलाओं में पढ़ो और अपने घर में पढ़ो।'

हिंदू अपने घर को कहते हैं मंदिर

नाजिया इलाही खान ने कहा कि, 'सबसे बड़ी बात है कि इस देश के 120 करोड़ हिंदू अपने घर को मंदिर कहते हैं। वे कहते हैं कि मेरा घर मेरा मंदिर है। तो आखिरकार मुसलमान अपने घर में ऐसी कौन सी अश्लीलता करते हैं जो वे अपने घर को अपनी मस्जिद नहीं समझ सकते हैं। घर से ज्यादा पाक और पवित्र जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है।'

पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता

(जीएनएस)।

पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बीच, भारत सरकार नियमित सूचनाओं के माध्यम से नागरिकों को सूचित रखने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। इसी क्रम में, आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक मीडिया प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने ईंधन की उपलब्धता, समुद्री संचालन और प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे उपायों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान की।

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धताः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वर्तमान ईंधन आपूर्ति स्थिति पर अद्यतन जानकारी दी। इसमें यह भी बताया गया किः

सार्वजनिक परामर्श एवं नागरिकों की जागरूकताः नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।

एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।

नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान स्थिति में अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करें।

सरकारी तैयारी और आपूर्ति प्रबंधन के उपायः मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी (परिवहन) की शत-प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है।

वाणिज्यिक एलपीजी के लिए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, प्रवासी श्रमिकों को 5 किलोग्राम एफटीएल की आपूर्ति 2 और 3 मार्च, 2026 को औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुनी कर दी गई है।

सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत प्रणालियों के साथ समन्वित प्रयासः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी और विनियमन में प्राथमिक भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार ने कई पत्रों और वीडियो संदेशों के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की पुष्टि की है।

भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 और 02.04.2026 के पत्रों के माध्यम से पर्याप्त ईंधन उपलब्धता के संबंध में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जनसंचार की आवश्यकता पर बल दिया है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में, 02.04.2026 (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में) और 06.04.2026 (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के साथ सूचना एवं प्रसारण एवं उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिवों की अध्यक्षता में) को बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गयाः

भूमि शासन एवं वाटरशेड प्रबंधन में सहयोग को लेकर भूमि संसाधन विभाग और एडीबी के बीच चर्चा

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, 21 मईः ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के सचिव श्री नरेन्द्र भूषण ने आज एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की कंट्री डायरेक्टर सुश्री मियो ओका के नेतृत्व में एडीबी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक परिचयात्मक बैठक की। बैठक के दौरान, श्री नरेन्द्र भूषण ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के सरकार के विजन के अनुरूप भूमि प्रशासन, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण और जलसंभर विकास के क्षेत्रों में भूमि संसाधन विभाग द्वारा की जा रही प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला।

सचिव ने कहा कि भूमि संसाधन विभाग को देश में भूमि अभिलेख प्रबंधन और भूमि प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि कुशल भूमि प्रशासन और भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग आर्थिक विकास को गति देने, भूमि संपत्तियों के मूल्य को उजागर करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

भूमि प्रशासन में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल देते हुए, श्री भूषण ने प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का डिजिटलीकरण लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि देश भर में लिखित भूमि अभिलेखों को जमाबंदी नक्शों से जोड़ने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं।

उन्होंने बताया कि विभाग कार्यक्रम के अगले चरण, डीआईएलआरएमपी 3.0 लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उपाय, भूमि अभिलेखों के गतिशील अद्यतन और भूमि संबंधी डेटाबेस के बेहतर एकीकरण के माध्यम से भूमि शासन प्रणालियों को और सुदृढ़ करना है।